

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *247
उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

डीएलआई तथा पीएलआई योजना

*247. श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय को डिजाइन-संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या सहित किए गए निवेश की राशि, सृजित रोजगार और उत्पादन तथा बिक्री सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से सफल रही हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा के दिनांक 20 दिसंबर, 2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *247 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में सदन के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) से (ड) सरकार भारत में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विनिर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है:

दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई:

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम जून, 2021 में शुरू की गई थी। बहुत कम समय के भीतर इसने भारत में दूरसंचार उपकरणों के उत्पादन को उत्प्रेरित किया है। विवरण निम्नानुसार हैं:

- कुल 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद।
- 4 से 7% तक का प्रोत्साहन
- पहले 3 वर्षों के लिए एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 1% प्रोत्साहन।
- 'भारत में डिजाइन किए गए' उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1% प्रोत्साहन।
- 28 एमएसएमई सहित कुल 42 आवेदक कंपनियां (अनुबंध के रूप में संलग्न)
- कुल वित्तीय परिव्यय: 12,195 करोड़ रुपये

दूरसंचार क्षेत्र में पीएलआई की अब तक की उपलब्धियां:

	आवेदकों द्वारा कुल प्रतिबद्धता	31 अक्टूबर, 2023 तक प्रगति
संचयी निवेश	4,014 करोड़	2,725 करोड़
वृद्धिशील बिक्री	2,37,807 करोड़	38,999 करोड़
अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार	44,494	15,561

- दूरसंचार पीएलआई स्कीम के तहत अब तक 8,804 करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात किया जा चुका है।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएलआई दूरसंचार स्कीम के तहत आज तक 34.97 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

टीटीडीएफ:

- सरकार ने दिनांक 01.10.2022 को दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) स्कीम शुरू की।
- टीटीडीएफ का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान और विकास को वित्तपोषित करना है।
- स्टार्ट-अप, एमएसएमई, शिक्षा जगत आदि से टीटीडीएफ स्कीम के तहत 405 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उचित मूल्यांकन के बाद अब तक 266.05 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 8 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इनमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मल्टीप्लेक्सिंग के साथ एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेस्ट बेड और 6जी टेरा हर्ट्ज टेस्ट बेड स्थापित करना शामिल है।

डीसीआईएस स्कीम:

- सरकार ने स्टार्ट-अप/एमएसएमई द्वारा नवीन विचारों और ज्ञान को व्यवहार में लाने को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए डिजिटल संचार नवाचार स्वचायर (डीसीआईएस) स्कीम शुरू की है।
- सरकार ने इस स्कीम के तहत सहायता अनुदान के रूप में अब तक 96 से अधिक स्टार्ट-अप/एमएसएमई को 74.7 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्रदान की है।
- ये इनोवेटर्स बैकहॉल रेडियो और संचार प्रौद्योगिकियों, एलटीई एडवांस्ड, 5जी/6जी और फ्यूचर जेनरेशन एक्सेस टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स (एसडीएन) आदि पर काम कर रहे हैं।

मेड इन इंडिया 5जी:

- भारत 14 महीने से भी कम समय में 4 लाख से अधिक साइटों को चालू करने के साथ दुनिया में 5जी का सबसे तेज रोल-आउट हुआ है।
- 5जी के रोल-आउट में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की एक बड़ी मात्रा 'मेड इन इंडिया' है।

स्वदेशी 5जी विकसित करना

- आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी 4जी/5जी दूरसंचार स्टैक विकसित किया गया है और बीएसएनएल नेटवर्क में स्थापित किया जा रहा है।

इकोसिस्टम का विकास:

भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को व्यापक और गहन बनाने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाना है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीमें (पीएलआई एलएसईएम और पीएलआई आईटी हार्डवेयर)
- इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (स्पेक्स)
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 (ईएमसी 2.0)
- इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए स्कीम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओसैट) और डिजाइन लिंकड इंसेंटिव (डीएलआई) स्कीमों की स्थापना की स्कीम कार्यान्वित की जा रही हैं।

सरकार की पहलों का प्रभाव:

- इन उपायों के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन 2014-15 में 1,80,454 करोड़ रुपये (29.8 बिलियन अमेरिकी डालर) से बढ़कर 2022-23 में 8,22,350 करोड़ रुपये (102 बिलियन अमेरिकी डालर) हो गया है।
- इसके अलावा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण साणंद, गुजरात में शुरू हो गया है।
- एक प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर शुरू किया है।
- एक अन्य प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में कुशल इंजीनियरों के एक बड़े पूल को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है।
- इसके अलावा मोबाइल उत्पादन वर्ष 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3,50,000 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2014 में लगभग 78% आयात निर्भरता से भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल का 99.2% 'मेड इन इंडिया' है।

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की पीएलआई स्कीम के तहत अनुमोदित कंपनियों का विवरण

क्रम सं.	आवेदक का नाम
1	एल्फियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	कैंडिड ऑप्टोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	कोरल टेलीकॉम लिमिटेड
4	डिजाइन और विनिर्माण विस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5	फ्रॉग सेलसैट लिमिटेड
6	गो आईपी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	कायनेस इंटरनेशनल डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
9	मैट्रिक्स कॉमसेक प्राइवेट लिमिटेड
10	समृद्धि ऑटोमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
11	संसैप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
12	विहान नेटवर्क्स लिमिटेड
13	डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	एचएफसीएल लिमिटेड
15	आईटीआई लिमिटेड
16	तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड
17	वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
18	इहूम आईओटी प्राइवेट लिमिटेड
19	एल्कॉम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
20	जीडीएन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
21	जीएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	ह्यूबर + सुहनर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
23	नेटलिंग आईसीटी प्राइवेट लिमिटेड
24	नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	पैनाचे डिजीलाइफ लिमिटेड
26	प्रियराज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
27	सिक्सथ एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	आवेदक का नाम
28	स्काईक्वाड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
29	सुरभि सैटकॉम प्राइवेट लिमिटेड
30	सिनेग्रा ईएमएस लिमिटेड
31	सिस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
32	टेक्निका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33	टियानयिन वर्ल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	कॉमस्कोप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35	फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
36	जबील सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
37	नियोलिंक टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
38	नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	राइजिंग स्टार्स हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड
40	सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
41	सनमिना-स्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42	सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड
